एआइ बताएगा राशन की गुणवत्ता, मॉनिटरिंग सिस्टम में होगा बदलाव

रियल टाइम में पता चल सकेगा कि अनाज कितने दिन भंडारण योग्य है

जितेन्द्र चौरसिया
patrika.com

नई दिल्ली. देश में 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए सस्ते और मुफ्त राशन की खरीदी में खराब गुणवत्ता और अरबों का लीकेज रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव होगा। पहली बार इस खरीद, वितरण व परिवहन में एआइ आधारित रियल टाइम कैप्चरिंग एनालिटिकल मोड लागू किया जाएगा। इसके तहत नई एडवांस तकनीक से सात लेयर में रियल टाइम कैप्चरिंग होगी, जिससे किसी भी वाहन में भरे अनाज के नीचे तक ऑटो ऑब्जर्व मोड में गुणवत्ता और मात्रा पता चल जाएगी।

गौरतलब है कि हाल में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स की रिपोर्ट में 69 हजार करोड़ के अनाज की लीकेज बताई गई थी। इसके बाद इस पूरी व्यवस्था में सुधार की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में 2 करोड़ टन से ज्यादा का अनाज लीकेज हुआ, जिसकी कीमत 69 हजार करोड़ से ज्यादा होती है।

खास बात है कि यह कुल खरीद का औसत 26 से 28 प्रतिशत है। बिकने या अवैध तरीके से निर्यात के दायरे में आता है। इसमें उत्तरप्रदेश में अनाज गरीबों को बांटने की समस्या भी बड़ी है। दोनों ही समस्याओं को

इस तरह काम करेगा सिस्टम

देश में अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए 550 से ज्यादा प्रमुख डिपो हैं। इनसे खरीदी-वितरण के लिए गेहूं-चावल लेकर ट्रक आते-जाते हैं। रेलवे रैक से भी परिवहन होता है। नए सिस्टम में एडवांस तकनीक को सभी वजन-तौल वाले एंट्री-एग्जिट पाइंट पर अपग्रेड किया जाएगा। इससे ट्रक-रैक के ऑटो वैट-काउंटिंग पॉइंट पर रियल टाइम गुणवत्ता व वजन कैप्चर होगा। ये सीधे मास्टर सर्वर तक अपलोड हो जाएगा। अभी इस गुणवत्ता-वजन को हर जगह कम्प्यूटर में फीड करना होता है, जिसे मास्टर सर्वर तक फीड होने में 24 से 48 घंटे तक का वक्त लग जाता है। नए सिस्टम में अनाज की आर्द्रता, तापमान सहित अन्य जानकारी भी सात लेयर में मिल जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि उसी वक्त यह जाना जा सकेगा कि ये अनाज कितने दिन भंडारण करने योग्य है या कब तक खराब होगा। यदि खराब है तो भी तुरंत मास्टर सर्वर तक इसकी जानकारी अपलोड हो जाएगी। इससे अनाज को बचाने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा एंट्री-एग्जिट के दो पाइंट के बीच मास्टर सर्वर पर रियल टाइम डाटा मिलने से लीकेज रूक सकेगा। अभी 65 से 70 प्रतिशत ह्यूमन हैंडलिंग है, जिसे नए सिस्टम में 20 से 25 प्रतिशत तक घटाया जा सकेगा।

कौन करेगा यह काम

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम मिलकर इस नए सिस्टम को क्रियान्वित करेंगे। इसमें सब्सिडी अनाज संचालन को तकनीक बेस्ड मॉनिटरिंग पर लाने के लिए काम हो रहा है। इसके लिए एक-एक साल के लक्ष्य लेकर काम होगा। अभी इस महीने मार्च 2026 तक के लक्ष्य तय किए हैं।

कितनी खरीद और बर्बादी

550 से ज्यादा डिपार्चर-रिसीविंग डिपो

360 **लाख** टन से ज्यादा गेहूं की सालाना खरीद

900 **लाख** टन से ज्यादा चावल की सालाना खरीद

69 **हजार करोड़** का होता है लीकेज रिपोर्ट के अनुसार

46% **अनाज** 2011-12 में बर्बाद होता था

28% **लीकेज** अभी 2024 में रिपोर्ट में

अभी यह हैं कमियां

- गुणवत्ता जांच की सीमित व्यवस्था
- मानक तय हैं, लेकिन सख्ती नहीं
- भ्रष्टाचार और मिलीभगत
- तकनीक का सीमित उपयोग
- लाभार्थियों की शिकायत